भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1922

11 फरवरी, 2026 के लिए प्रश्न

मिजोरम में पीडीएस और तेल डिपो अवसंरचना

1922. श्री रिचर्ड वनलालह्मंगइहा:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मिजोरम राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के कामकाज और आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता की समीक्षा की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त राज्य में विशेषकर दूरस्थ और सीमावर्ती क्षेत्रों में नियमित मांग और आपातकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त तेल डिपो और ईंधन भंडारण अवसंरचना (पेट्रोल, डीजल और एलपीजी भंडारण सहित) उपलब्ध हैं;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का मिजोरम में नए तेल डिपो स्थापित करने या मौजूदा सुविधाओं का उन्नयन करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो प्रस्तावित समय-सीमा सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क): जी हाँ। सरकार मिजोरम में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के कामकाज और आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता की निरंतर समीक्षा करती है।

तकनीकी सुधारों के अंतर्गत, पीडीएस के संपूर्ण कम्प्यूटरीकरण की योजना पूरे देश में लागू की गई है। राष्ट्रीय स्तर पर राशन कार्डों के 100% डिजिटलीकरण, इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ सेल (ई-पीओएस) उपकरणों की संस्थापना, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के कार्यान्वयन, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के कम्प्यूटरीकरण, ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणालियों और पारदर्शिता पोर्टलों की शुरुआत के संदर्भ में महत्वपूर्ण प्रगति प्राप्त की गई है और यह पोर्टल आधार-बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के माध्यम से देश में एनएफएसए लाभार्थियों को पारदर्शिता और सही प्रकार से लक्षित करने को सुनिश्चित करते हैं।

...2/-

(ख) से (घ): सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम तेल विपणन कंपनियों (पीएसयू ओएमसी) द्वारा नए तेल टर्मिनलों/डिपुओं की स्थापना, खुदरा आउटलेट नेटवर्क का विस्तार और द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) वितरकों की नियुक्ति, देश भर में मोटर स्पिरिट (एमएस), हाई स्पीड डीजल (एचएसडी) और एलपीजी सहित पेट्रोलियम उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एक सतत प्रक्रिया है, जो किसी विशेष क्षेत्र की आवश्यकता के अनुसार वैधानिक मानदंडों की पूर्ति और व्यावसायिक व्यवहार्यता को ध्यान में रखते हुए की जाती है।

दिनांक 01.02.2026 तक, पीएसयू ओएमसी के पास मिजोरम में ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों सहित 117 खुदरा आउटलेट (आईओसीएल-77, बीपीसीएल-15 और एचपीसीएल-25) परिचालन में हैं। इसके अलावा, पीएसयू ओएमसी के पास मिजोरम में उपभोक्ताओं की घरेलू एलपीजी आवश्यकता को पूरा करने के लिए कुल 59 एलपीजी वितरक हैं। इस प्रकार, नियमित और आपातकालीन दोनों आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमता मौजूद है।

*****